जशपुर-गुमला तार लाइन

2493. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और बिहार के बीच स्थापित जशपुर-गुमला तार लाइन का कार्य पिछले दस वर्षों से बन्द पड़ा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और बिहार के लिये तार भेजे जाने के लिये किस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इस तार लाइन को चालू करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां । यह लाईन 1986 से बन्द है ।

(ख) तार के बार-बार चोरी होने के कारण इस लाइन में गंभीर व्यवधान हुये हैं जिसने इस तार सर्किट को निष्क्रिय बना दिया था । अब, जशपुर को रायगढ़ स्टीर एंड फारवर्ड टेलेक्स (एस.एफ.टी.) केन्द्र तथा गुमला को रांची केन्द्र से जोड़ दिया गया है । जशपुर और गुमला में भेजे जाने वाले/प्राप्त होने वाले तार इसी व्यवस्था के तहत भेजे जाते हैं ।

(ग) जशपुर और गुमला के बीच तार परियात के संचालन के लिये पहले से की गई वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये ऊपर (ख) में उल्लिखित तथा इस लाइन के अकुशल रख-रखाव के कारण इस तार लाईन को पुनः चालू करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

Expansion and Modernisation Plan of MTNL

2494. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

SHRIMATI VEENA VERMA:

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether M.T.N.L. has launched an expansion and modernisation plan for the period 1993 to 1994; and

(b) if so, what are the salient features of the plan and what is the cost thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) Tentatively it is proposed to provide net switching capacity of 136000 lines at MTNL Delhi and 159000 lines at MTNL Bombay during 199-94. An amount of Rs. 967 crores is being provided to meet annual plan requirements of MTNL for 1993 94.

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पूल से प्राथमिकता के आधार पर आवास का आवंटन

2495. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन्स में पांच वर्षों की सेवा के पश्चात महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने वाले इन कर्मचारियों को निगम पूल से प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक आवास आवंटित किये गये हैं जिन्हें पहले से ही आवास प्राप्त थे ;